



पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

सूचना का अधिकार मामला

समयबद्ध

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

चीन प्रभाग

02 मार्च, 2017

सं. ई/551/ 12 /2017-आरटीआई

सेवा मे,

श्री दीपक रजन
प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया
पीटीआई बिल्डिंग
4, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

विषय: सूचना का अधिनियम 2005, के अंतर्गत माँगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 21.02.2017 का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था।

2. चाही गई जानकारी विदेश मंत्रालय द्वारा संसद के प्रश्नों के दिए गए उत्तर जो कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.meaindia.gov.in पर उपलब्ध है, मैं देखे जा सकते हैं। हाल ही मैं इस मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दिए गए प्रश्न क्रमांक 816 (आतंकवादी गुटों के संबंध में भारत को चीन की सलाह) का उत्तर इस पत्र के साथ संलग्न है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

अवदीय

प्रसन्न श्रीवास्तव

(प्रसन्न श्रीवास्तव), IFS

उपसचिव (चीन और कोरिया), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्री मुकेश कुमार अम्बास्ता, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

165

323/2017

सेवा में,

ग्रन्थालय

केन्द्रीय जनधर्म के अधिकारी
 निदेश भैजाला, भारत सरकार
 जनाधर लाल नैदर्ख भवन, जनधर रोड
 नई दिल्ली - 110001

872

21/02/17

विषय : आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु

महोदय,

सचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, इसके लिए 10 रुपये का पोस्टल आईर शुल्क के रूप में संलग्न कर रहा है जिसकी संख्या है।

1 खंखार आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों की सूची में शामिल कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है।

2 चीन ने इस बारे में भारत के प्रयासों का कितनी बार विरोध किया।

3 भारत सरकार इस मामले में क्या चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है।

4 मुम्बई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद और 1993 के मुम्बई सिलसिलेबार बम विस्फोट के अपराधी दाउद इब्राहम को देश में वापस लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है।

प्रभाग
165
US (पार्स) - 11
US (चीन) - 21
US - 20/2

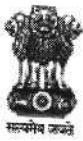
आपका विश्वासी

दीपक रंजन
 प्रेस टेस्ट आफ इंडिया
 पीटीआई बिल्डिंग
 4, संसद मार्ग
 नई दिल्ली 110001

ई मेल. dipakranjan@rediffmail.com

मोबाइल . 9911918723

10/RTT
4/1
Mr. Dipak



विदेश मंत्रालय

भारत सरकार

होम , मीडिया सेंटर/दस्तावेज़ , संसदीय प्रश्न एवं उत्तर , राज्य सभा

प्रश्न सं. 816 आतंकवादी गुटों के संबंध में भारत को चीन की सलाह

फरवरी 09, 2017

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 816

09.02.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

आतंकवादी गुटों के संबंध में भारत को चीन की सलाह

816. श्री टी. रतिनावेल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत को राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद का उल्लेख नहीं करने की सलाह दी है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि यह सलाह पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुटों के प्रमुखों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने की भारत की मांग की पृष्ठभूमि में दी गई है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों के संबंध में भारत के पक्ष पर चीनी प्राधिकारियों के संदेह को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का व्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[जनरल (डा.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त)]

(क) से (घ) चीन ने कई अवसरों पर आतंकवाद के फैलाव पर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए इस मुद्दे पर भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। चीन ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के लिए 'जीरो टॉलरेंस' के साथ अपना दृढ़प्रतिज्ञ विरोध जताया है, और इस बात पर सहमत हुआ है कि आतंकवाद को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।

सरकार ने पाकिस्तान की ओर से सीमापार से उत्पौन्न आतंकवाद के खतरे के मामलों को चीन के साथ दृढ़तापूर्वक और लगातार उठाया है, जिससे भारत सहित पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। खासकर हमने बल देकर कहा है कि जबकि पाकिस्तान में जड़ें जमाए जैश-ए-मोहम्मद पर उसकी कुख्यात आतंकवादी द्वारा वर्ष 2001 में ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य सरगना, वित्तपोषक और प्रेरक मसूद अजहर की नामजदगी पर लगातार निर्णय लिया।

इसी प्रकार पहले भी हमने लश्कर-ए-तैयबा के सरगनाओं जाकिर उर रहमान लखवी और हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के रहनुमा सथैद सलाहुद्दीन सहित कुख्यात आतंकवादियों पर 1267 यूएन प्रतिबंध समिति में कार्रवाई की मांग की थी और चीन के आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' के घोषित रुख और भारत के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत बनाने की उसकी इच्छा के अनुसार चीन से भारत के अनुरोध का समर्थन करने का अनुरोध किया है। भारत के अनुरोध को 1267 प्रतिबंध समिति सहित व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है। तथापि चीन ने भारत के अनुरोध का समर्थन नहीं किया और इस मामले में तकनीकी अड़चने पैदा करते हुए 1267 समिति की कार्रवाई में प्रतिरोध उत्पन्न किया।

सरकार सभी उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करके आतंक हिंसा के अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ संकल्प के साथ निरंतर प्रयासरत है।



© विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वामित्व सामग्री.

संदर्भ और शर्तें गोपनीयता नीति अधिकार नीति हाइपरलिंकिंग नीति अभिगम्यता वक्तव्य सहायता

उपयोगकर्ता: 87616138 अंतिम नवीनीकृत: 9-2-2017